drugs is to have a massive increase in pharmaceutical proudcts because we have an excellent pharmaceutical industry, and if they are given adequate incentives, we can have a massive increase in our pharmaceutical products, which we can also export. As the opposite side of spurious drugs, is the Government taking any steps to encourage and extend the drug industry as such, so that this meance is automatically met?

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति जी, मैं डा. कर्ण सिंह जी की बात से बिलकुल सहमत हूं कि एक दूसरा तरीका भी इस को रोकने का है कि ड्रग इंडस्ट्री को इंसेटिव दिया जाए। मुझे खुशी है यह बताते हुए कि तीन दिन पहले जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है,उसमें उन्होंने खास तौर पर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री का जिक्र किया है और यह कहा है कि साथ में वे तमाम इंसेंटिव्ज जो आई.टी. में दिए जाते है, वे उन्होंने हमारी ड्रग इंडस्ट्री को देने की बात कही है। इसलिए जो सुझाव आपने आज दिया है उस सुझाव को पहले ही इस बजट में अमल में ला दिया गया है।

पत्रकारों के लिए बीमा योजना

*164. **श्री पी. के. माहेश्वरी :**
श्री रामचन्द्र खूंटिआ :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्रकारों के लिए कोई बीमा योजना बनाई है,

(ख) यदि हां, तो इस बीमा योजना में क्या प्रावधान है और उनसे पत्रकारों को कितना लाभ मिलेगा ,

(ग) इस योजना में किस श्रेणी के पत्रकारों को शामिल किया गया है,और

(घ) क्या सरकार पत्रकारों को 'रिपोर्टर' या 'संवाददाता' की श्रेणी में मान रही है जो 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं और उनको बीमा योजना में शामिल किया जाता है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (घ) बीमा कम्पनी द्वारा पत्रकारों के लिए एक उपयुक्त स्कीम बनाने की प्रक्रिया को सरल एंव कारगर बनाने के लिए जीवन बीमा निगम से प्रारंभिक विचार-विमर्श किए गए हैं।

सभा में यह प्रश्न श्री पी. के. माहेश्वरी द्वारा पूछा गया।

Insurance scheme for Journalists

†164. SHRI P. K. MAHESHWARI:††
SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any Insurance Scheme for Journalists;

(b) if so, the provisions of this scheme and to what extent Journalists are likely to be benefited therefrom;

(c) the category of Journalists covered under the scheme; and

(d) whether Government are considering the Journalists in the category of Reporters or Correspondents who discharge their duties round the clock are covered under the insurance scheme?

THE MINISTER OF STATE OFTHE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): (a) to (d) Preliminary discussions have been held with LIC with a view to facilitating formulation by the insurance company, of a suitable scheme for Journalists.

SHRI R K. MAHESHWARI: Madam, I am very happy that the Minister has considered it, and has held discussions with the LIC for formulation of a suitable scheme. I would like to know from the Minister what are the details on which this scheme is being formulated. As we know, the profession of journalists has become a very hazardous one. They are beaten up, assaulted and even murdered in the line of their duty. Will the Minister tell us who are the people who are to be covered under this scheme? Will the Government also contribute some amount to this scheme? ...*(Interruptions)*...

उपसभापति : आप जरा छोटा सवाल पूछेंगे तो बड़ा जवाब आ सकता है।

श्री पी.के. माहेश्वरी : मैडम, मुझे बस यही पूछना था कि कौन-कौन से लोग इस स्कीम में रहेंगे? क्या केवल जो रिपोर्टर्स हैं, वे ही इसमें रहेंगे या बाकी सारे जर्नलिस्ट्स के लिए भी यह स्कीम लागू होगी ?

---

†Orlglnal notice of the question was received in Hindi.
††The question was actually asked on the floor of the House by Shri R K. Maheshwarl.

श्री रवि शंकर प्रसाद : उपसभापति जी, सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और उनके जीवन को सुविधा देने के लिए कृतसंकल्प है । हमने अलग से एक जर्नलिस्ट्स वेलफेयर फंड बनाया है जिसका पूरा अनुदान सरकार ने दिया है । वह पांच करोड़ की राशि है । इसमें असामयिक मृत्यु या अपाहिज होने की स्थिति में हम फंड्ज देते हैं। जहां तक बीमे का सवाल है, इस विचार को भी सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है । सरकार सुविधाजनक वातावरण बना सकती है, जहां तक उसके डीटेल्स का प्रश्न है, वह ग्रुप इंश्योरेंस हो, मालिक और पत्रकारों के बीच उसको हम कैसे वर्कआउट करें, यह डीटेल्स का विषय है । जिसके लिए हमने एल.आई.सी. से पहल की है। एल.आई.सी. से जो अभी आरम्भिक बातचीत हुई है उसमें उन्होंने एक स्तर बनाया है । हमने कहा कि उसको और व्यापक करिए और उसकी उम्र सीमा को भी आगे बढ़ाइए ताकि पत्रकारों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके । सरकार अपना सहयोग करेगी लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ग्रुप इंश्योरेंस हो या इंडिविज्युअल इंश्योंरेंस हो इसमें मालिकों की भी भूमिका होगी, इसमें पत्रकारों की भी भूमिका होगी । जब इसका विस्तृत डिटेल बन जाएगा तो मैं विस्तार से सारे मालिकों से, सारे पत्रकारों के संगठनों से भी बातचीत करूंगा ।

SHRI P.K. MAHESHWARI: Madam I would also like to know from the hon. Minister whether this would be extended to all those people who are working in the rural areas, especially in the far-flung areas away from the capital; and, whether the State Governments will also be encouraged to implement this Scheme.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, as far as this question is concerned, it is a matter of detail. But, let me share with this hon. House that we have got certain journalists who are accredited in Delhi. We have got the accreditation process in the State capitals also.The number in the State capitals is fairly wide, about 7,500 to 8,500. In Delhi, it is about 1,500. As far as the correspondents in the far-flung areas are concerned, they also belong to two categories; some are lawyers and some are teachers. They are also part-time journalists. All these are matters of details, to be worked out. Again, I would repeat that after this scheme comes about, we shall certainly have a fairly wide-scale interaction. But, let me again tell the hon. House that the owners of the newspapers will also have to play a crucial role.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ramachandra Khuntia.This is an indication.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Madam Deputy Chairman, this

is a very serious thing. Only a few days ago, on 24th, Shri Chowdhary, a Deputy News Editor, died in Rajasthan in a car accident. One Special Correspondent of The Hindu', Shri Ramdas from Orissa, died InTirupati. We also know that those who were going with Mr. Madhavrao Scindia met with an accident, and three of them died. It is a matter of serious Concern. The question is whether the Government is taking the matter in all its sincerity and seriousness. The journalists are dying on the border; they are dying here in Delhi and everywhere. The question is whether the Government has made any assessment as to how many journalists are working in Delhi, in State capitals and in the whole of the country. The Government should have the statistics before formulating a scheme. What is more important is to know the number of journalists working in the whole of the country. If the Government has no statistics, how could a policy could be formulated? I want to know from the Government whether the Government has statistics about this and ...*{Interruptions).*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him answer first about statistics.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam. I would like to inform the hon. Member that his concern that we are not serious is entirely misplaced, this scheme for the welfare of journalists was initiated by our Government, by my learned predecessor. This whole scheme of insurance has been initiated by our Government. This, by itself, is indicative of the fact that our Government is committed to the security and well-being of all the journalists. As far as details are concerned, as I indicated in reply to the first question, there are about 1,400 accredited journalists, as far as Delhi is concerned. Their number varies from 7,500 to 8,500 in State capitals.These are matters of detail. We are working it out with the insurance company, and once the details are worked out, we will do our best and the Government is committed, as I said earlier, to the well-being and security of the working journalists.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Shahid Siddiqui ...*{Interruptions)*

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Madam, one more question, please.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can't. Only one question is allowed. The second questioner can only have one supplementary. Let other hon. Member put questions.

श्री शाहिद सिद्दकी : मंत्री जी, आपने एक्रेडिटेड जर्नलिस्टों की बात की है। लेकिन आप जानते हैं कि शायद दो प्रतिशत भी जर्नलिस्ट एक्रेडिटेड नहीं होते है। उनको फेसिलिटी मिलती हैं। लेकिन किसी भी संगठन में जो 98 प्रतिशत पत्रकार होते हैं उन्हें वह फेसिलिटी नहीं मिल पाती । इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूगा कि आप उन जर्नलिस्टों की तरफ ध्यान करें स्टेट में या कैपिटल में जिनको एक्रेडिशन नहीं मिला हुआ है। खास तौर पर जो लेंग्युएज जर्नलिस्ट हैं वे इसका शिकार बनते हैं । तीसरे इलेक्ट्रोनिक मीडिया जो आज बहुत ज्यादा बढ़े हैं जिसने तरक्की की हैं, उनकी जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जिंदगी ज्यादा दांव पर रहती है । यह पूरा प्रोफेशन एक टेन्शन और दबाव का है । इसमें जर्नलिस्टों की सेहत का भी .....

उपसभापतिः आप थोड़ा संक्षेप में पूछ लें।

श्री शाहिद सिद्दिकी : ध्यान रखना होता है । इसलिए मैं आपसे पूछंगा कि इनके लिए क्या हैल्थ फैसिलिटीज के लिए कोई स्कीम बनाई है ताकि इंश्यारेंस के अलावा भी उनकी सेहत के लिए सरकारी अस्पतालों से और दूसरे अस्पतालों से सस्ती और मुफ्त मैडिकल फैसिलिटी मिल सके क्योंकि एक बहुत दबाव पत्रकारों के ऊपर रहता है ।

श्री रवि शंकर प्रसाद : उपसभापति महोदय मैंने यह कभी नहीं कहा कि सिर्फ एकरेडिटिड जर्नलिस्ट का ही हम यहां विचार करेंगे । क्योंकि माननीय सदस्य ने एक संख्या के बारे में पूछा है कि हमने वर्क आउट क्या किया है? हमने उसके बारे में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है। जहां तक नोन एकरेडिटिड जर्नलिस्ट का सवाल है, यह एक विस्तार की बात है । जब यह योजना सामने आएगी तो हम इन सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देंगे । लेकिन आपने जो स्वास्थ्य सेवा के बारे में बात कही हैं यही सही है कि जब ऐक्रोडिटेशन हो जाता है तो सीजीएचएस की सुविधा मिलती है । इसके बारे में और क्या सुविधा हो सकती है यह एक विचार का प्रश्न है । लेकिन जो बीमा योजना है, वह सारे दृष्टिकोण का विचार करती है। इसलिए जहां तक हमारे वेलफेयर फंड की बात है आपने जो परेशानी की बात बताई देश के जिन आठ पत्रकारों की असामयिक मृत्यु हुई, उनको तुरन्त इस फंड से फायदा दिया है । हमारे पास आठ जर्नलिस्टों के नाम हैं । ऐसे और जर्नलिस्ट जो खतरे में पड़ेंगे हम उनकी भी चिंता करेंगे । यह मैं आपको बताना चाहता हूं ।

SHRIKARTAR SINGH DUGGAL: Madam. I would like to know from the hon. Minister whether this scheme has any provision for its extension to other cultural writers, like creative writers, theatre workers, film workers and so on.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam I would like to inform the hon. Member that, presently, the journalists are engaging our attention. As far as the workers engaged in other creative fields are concerned, it is

an issue, which is certainly there. But presently, the Government is considering only this issue. If some details come about, we will look into it.

Mobile Diagnostic Treatment Clinics in Rural Areas

*165 MISS MABEL REBELLO: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there are mobile Diagnostic treatment Clinics in the rurai areas run either by Central or State Governments;

(b) if so, the details thereof, State-wise;

(c) whether these clinics have the required number of staff and medicines; and

(d) the number of patients attended by these mobile clinics during the last three years, State-wise?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATi SUSHMA SWARAJ): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The Central Government has no scheme under which Mobile Diagnostic Treatment Clinics are being run in rural areas. However, under the National Programme for control of Blindness, upto the tXth five year plan, assistance was provided for 344 disthcts mobile ophthalmic units and 80 central mobile ophthalmic units to screen the patients, provide treatment for minor eye ailments and undertake cataract surgery. State-wise details fo these units are at Statement-I. *{See* below) For each of these units, staff consisting of an eye surgeon, ophthalmic assistant, camp coordinator, staff nurse and one driver and one attendant were sanctioned alongwith drugs, medicines and equipments as required. Since the IXth Plan, with the change instrategy, mobile clinics are being used for screening patients and bringing those requiring cataract surgery to base hospitals. It is estimated that on an averae, these Mobile Units conduct almost 6% of the total cataract surgeries performed in the country. The target beneficiaries are essentially the old and infirm.